

भारत - चीन संबंध

राजनीतिक संबंध

1 अप्रैल, 1950 को भारत चीन जनवादी गणराज्य के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला पहला गैर समाजवादी ब्लाक का देश बना। प्रधानमंत्री नेहरू ने अक्टूबर, 1954 में चीन का दौरा किया। हालांकि 1962 में भारत - चीन सीमा संघर्ष संबंधों के लिए एक गंभीर आघात था, परंतु प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की 1988 में महत्वपूर्ण यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के चरण की शुरुआत हुई। 1993 में प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव की चीन यात्रा के दौरान भारत - चीन सीमा क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एल ए सी) पर शांति एवं अमन - चैन बनाए रखने के लिए करार पर हस्ताक्षर ने द्विपक्षीय संबंधों में बढ़ती स्थिरता एवं महत्व को प्रतिबिंबित किया।

राष्ट्राध्यक्षों / शासनाध्यक्षों के स्तर पर यात्राएं :

हाल के वर्षों में नौ प्रमुख यात्राओं के संचयी परिणाम से हमारे संबंधों में बदलाव आए हैं। इन यात्राओं में प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की 2003 में चीन यात्रा, प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ की 2005 और 2010 में भारत की यात्रा, राष्ट्रपति हू जिंताओ की 2006 में भारत यात्रा, प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह की 2008 और 2013 में चीन यात्रा, प्रधानमंत्री ली किचियांग की 2013 में भारत यात्रा तथा राष्ट्रपति शी जिनपिंग की 2014 में भारत एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 2015 में चीन यात्रा शामिल है।

प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की चीन यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने संबंधों एवं व्यापक सहयोग के लिए सिद्धांतों पर एक घोषणा पर हस्ताक्षर किया तथा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से सीमा प्रश्न के समाधान के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के लिए विशेष प्रतिनिधि (एस आर) नियुक्त करने का भी परस्पर निर्णय लिया। अप्रैल, 2005 के दौरान, प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ की भारत यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने शांति एवं समृद्धि के लिए एक सामरिक एवं सहयोग साझेदारी स्थापित की, जबकि राजनीतिक पैरामीटरों एवं मार्गदर्शक सिद्धांतों पर एक करार पर हस्ताक्षर ने एस आर वार्ता के पहले चरण की सफल समाप्ति का संकेत दिया। नवंबर, 2006 में चीन के राष्ट्रपति हू जिंताओ की भारत यात्रा के दौरान, दोनों पक्षों ने एक संयुक्त घोषणा जारी की जिसमें सहयोग को गहन करने के लिए 10 सूत्रीय रणनीति का उल्लेख है। प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने जनवरी, 2008 में चीन की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान "21वीं शताब्दी के लिए एक साझा विजन" शीर्षक से एक संयुक्त दस्तावेज जारी किया गया। जब चीन के प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ दिसंबर, 2010 में भारत के दौरे पर आए थे तब दोनों पक्षों ने दोनों

देशों के विदेश मंत्रियों के बीच यात्रा के वार्षिक आदान प्रदान के तंत्र को स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की थी।

चीन जनवादी गणराज्य की राज्य परिषद के प्रधानमंत्री श्री ली किचियांग ने 19 से 21 मई, 2013 के दौरान भारत (दिल्ली - मुंबई) का राजकीय दौरा किया। इस यात्रा के दौरान, दोनों पक्षों ने आठ करारों पर हस्ताक्षर किए तथा एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। संयुक्त वक्तव्य में जिन महत्वपूर्ण प्रस्तावों को शामिल किया गया उनमें से कुछ इस प्रकार हैं : वर्ष 2014 को भारत और चीन के बीच मैत्रीपूर्ण विनिमय वर्ष के रूप में घोषित करना तथा उच्च स्तरीय मीडिया मंच की पहली बैठक का आयोजन करना।

पूर्व प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने 22 से 24 अक्टूबर, 2013 के दौरान चीन का आधिकारिक दौरा किया। सीमा, सीमापारीय नदियों, भारत में विद्युत उपकरणों की मरम्मत के लिए सेवा केंद्र स्थापित करने, सड़क परिवहन तथा नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित करारों पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अलावा, दिल्ली - बीजिंग, कोलकाता - कुनमिंग और बंगलौर - चेंगडु के बीच सिस्टर सिटी साझेदारी स्थापित करने के लिए तीन करारों पर भी हस्ताक्षर किए गए।

उप राष्ट्रपति माननीय श्री हामिद अंसारी ने 20 से 26 जून, 2014 के दौरान चीन का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान उप राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की, उप राष्ट्रपति लिउ युवांचाओ के साथ बातचीत की, पंचशील की 60वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रमों में भाग लिया तथा शांशी प्रांत में झियान का दौरा किया। औद्योगिक पार्क, सरकारी अधिकारियों का प्रशिक्षण तथा यारलुंग जांगबु नदी पर बाढ़ के मौसम के दौरान डाटा के आदान - प्रदान से संबंधित तीन करारों पर हस्ताक्षर किए गए। दो उप राष्ट्रपतियों ने संयुक्त रूप से भारत - चीन सांस्कृतिक संपर्क के विश्वकोष के अंग्रेजी एवं चाइनीज संस्करण का विमोचन किया।

चीन के राष्ट्रपति श्री शी जिनपिंग ने 17 से 19 सितंबर, 2014 के दौरान भारत का राजकीय दौरा किया। यात्रा के दौरान, राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की तथा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत की। इस यात्रा के दौरान, विभिन्न क्षेत्रों में कुल 16 करारों पर हस्ताक्षर किए गए जो इस प्रकार हैं : वाणिज्य एवं व्यापार, रेलवे, अंतरिक्ष सहयोग, भेषज पदार्थ, श्रव्य - दृश्य सह-निर्माण, संस्कृति, औद्योगिक पार्कों की स्थापना, सिस्टर सिटी व्यवस्था आदि।

दोनों पक्षों ने नथुला पास से होते हुए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक अतिरिक्त मार्ग खोलने के लिए एक एम ओ यू पर भी हस्ताक्षर किया। चाइनीज पक्ष भारत में दो चाइनीज

औद्योगिक पार्क स्थापित करने पर सहमत हुआ तथा भारत में चीनी निवेश बढ़ाने के लिए अपनी मंशा व्यक्त की।

मई, 2015 में प्रधानमंत्री का चीन दौरा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 14 से 16 मई तक चीन का दौरा किया, प्रतीक एवं सार की दृष्टि से यह यात्रा बहुत ही समृद्ध थी तथा इसने भारत - चीन संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत की। पहली बार चीन के राष्ट्रपति शी जिंगपिंग ने किसी विदेशी नेता की शियान में शांशी के अपने गृह प्रांत में अगवानी करने के लिए बीजिंग से बाहर का दौरा किया। राष्ट्रपति शी प्रधानमंत्री मोदी के साथ बिग वाइल्ड गूज पगोडा भी गए तथा शियान सिटी वाल में एक भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया। प्रधानमंत्री ली कीक्यांग पृष्ठभूमि के रूप में टेम्पल ऑफ हैवन के विश्व विरासत स्थल के साथ 15 मई को बीजिंग में योग - ताइची परफार्मेंस में प्रधानमंत्री मोदी के साथ भाग लिया, जो इस तरह का पहला कार्यक्रम था जिसमें दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संपर्क को उजागर किया गया।

सरकार दर सरकार स्तर पर 24 करार, व्यवसाय दर व्यवसाय स्तर पर 26 एम ओ यू तथा दो संयुक्त वक्तव्यों पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें से एक जलवायु परिवर्तन पर था। यह तथ्य कि भारत और चीन मात्र 8 महीने की अवधि में 50 से अधिक परिणाम दस्तावेजों के साथ आ सकते हैं, हमारे दोनों देशों के बीच मौजूद विशाल संभावना के अलावा उन प्रयासों को दर्शाता है, जिन्हें हम अपनी साझेदारी के स्तर को ऊपर उठाने के लिए कर रहे हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री ली ने कहा, अंतर-सरकारी करारों के तहत स्वर्ग से पृथ्वी तक के क्षेत्र शामिल हैं। इनमें अंतरिक्ष सहयोग, भूकंप इंजीनियरिंग, महासागर विज्ञान, खनन, रेलवे, कौशल विकास, शिक्षा, संस्कृति, योग, पर्यटन जैसे विविध क्षेत्रों के अलावा अनेक अन्य क्षेत्र शामिल हैं। शंघाई में कारोबारी कार्यक्रमों से हमारी आर्थिक साझेदारी की ताकत का आकलन किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने चीन की अग्रणी कंपनियों के 21 सी ई ओ के साथ बातचीत की तथा कारोबारी मंच में चीन से अपने समकक्षों के साथ भारत के 40 प्रख्यात सी ई ओ ने भाग लिया। फोरम में 22 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक मूल्य के 26 कारोबारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत औद्योगिक पार्क, नवीकरणीय ऊर्जा, थर्मल ऊर्जा, दूरसंचार, इस्पात, पूंजी माल, आई टी तथा मीडिया जैसे विविध क्षेत्र शामिल थे। इसके अलावा द्विपक्षीय व्यापार में विद्यमान असंतुलन को दुरुस्त करने तथा इसमें संपोषणीयता के तत्व को शामिल करने पर दोनों देशों के नेताओं के बीच स्पष्ट सहमति थी। इसे ध्यान में रखकर वे एक उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल स्थापित करने

पर सहमत हुए जो व्यापार घाटे से संबंधित मुद्दों तथा आर्थिक भागेदारी के विस्तार से संबंधित मुद्दों की जांच करेगा।

इसके अलावा द्विपक्षीय साझेदारी को विस्तृत करने पर कार्य उन्मुख सहमति थी, जिसे हस्ताक्षरित किए गए करारों की रेंज से और नए वार्ता तंत्रों की स्थापना से महसूस किया जा सकता है, जैसे कि डी आर सी नीति आयोग के बीच वार्ता तंत्र और थिंक टैंक फोरम के अलावा डब्ल्यू टी ओ वार्ता पर द्विपक्षीय परामर्श तंत्र। साझेदारी में तीन नई संस्थाई शुरू की गईं, शांघाई में गांधीवादी और भारतीय अध्ययन केन्द्र, कुनमिंग में योग महाविद्यालय और अहमदाबाद में राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता संस्थान।

दोनों पक्षों ने एक दूसरे के देश में चेंगदू एवं चेन्नई में नए कॉन्सुलेट स्थापित करने और उप राष्ट्रीय स्तर पर हमारी बातचीत का विस्तार करने का निर्णय लिया। दो करारों पर हस्ताक्षर किए गए - एक भारत के विदेश मंत्रालय और सी पी सी की केन्द्रीय समिति के अंतर्राष्ट्रीय विभाग के बीच और दूसरा राज्य / प्रांतीय नेता मंच की स्थापना पर करार - जो इस सहमति को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी तथा प्रधानमंत्री ली ने 15 मई को बीजिंग में नए फोरम के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया, जो यह देखते हुए एक महत्वपूर्ण पहल है कि पहली बार भारत ने किसी देश के साथ इस तरह का वार्ता तंत्र स्थापित किया है। निम्नलिखित शहरों के बीच सिस्टर-सिटी और सिस्टर-राज्य संबंध करार पर भी हस्ताक्षर किए गए : कर्नाटक और सिचौन, चेन्नई और छोंगकिंग, हैदराबाद और किंगडाओ, औरंगाबाद और दुनहुआंग।

प्रधानमंत्री ने भारत का दौरा करने के इच्छुक चीन के नागरिकों के लिए ई-वीजा सुविधा प्रदान करने की भी घोषणा की। प्रधानमंत्री ने सिंधुवा विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित किया तथा शांघाई में भारतीय समुदाय द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में भाषण भी दिया जो इस क्षेत्र में समुदाय की अब तक की सबसे बड़ी गैदरिंग थी।

इस यात्रा से भारत और चीन के बीच सहयोग के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक संदेश भी मिला। नेताओं के बीच इस बात पर सहमति थी कि हमारा संबंध एशिया में और इससे आगे भी 21वीं शताब्दी में एक निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तैयार है, तथा यह स्वीकार किया गया कि दो प्रमुख महाशक्तियों के रूप में एक साथ भारत और चीन के पुनः उद्भव का इस शताब्दी पर प्रचुर प्रभाव होगा। संयुक्त वक्तव्य में "क्षेत्रीय एवं वैश्विक एजेंडा को आकार देना" पर अलग से एक खंड है जहां वैश्विक वास्तुशिल्प में दो प्रमुख ध्रुव के रूप में भारत और चीन डब्ल्यू टी

ओ, जलवायु परिवर्तन तथा आतंकवाद और क्षेत्रीय संगठन जैसे अनेक मुद्दों पर सहयोग करने के लिए सहमत हैं।

उच्च स्तर पर हाल की अन्य यात्राएं :

चीन के विदेश मंत्री श्री वांग यी ने 8-9 जून, 2014 को चीन के विशेष दूत के रूप में भारत का दौरा किया। यात्रा के दौरान, उन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश मंत्री से मुलाकात की।

विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने भी म्यांमार में आसियान क्षेत्रीय मंच के दौरान अतिरिक्त समय में अगस्त में चीन के विदेश मंत्री श्री वांग यी से मुलाकात और फिर सितंबर, 2014 में न्यूयार्क में यू एन जीए सत्र के दौरान अतिरिक्त समय में उनसे मुलाकात की।

माननीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने 1 से 3 फरवरी, 2015 के दौरान चीन जनवादी गणराज्य का आधिकारिक दौरा किया जिसके दौरान उन्होंने चीन के राष्ट्रपति श्री शी जिनपिंग से मुलाकात की, विदेश मंत्री श्री वांग यी के साथ औपचारिक बातचीत की और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के अंतर्राष्ट्रीय विभाग मंत्री श्री वांग जियारूई के साथ भी बैठक की। विदेश मंत्री महोदया ने द्वितीय भारत - चीन उच्च स्तरीय मीडिया मंच का भी उद्घाटन किया तथा बीजिंग में अपने प्रवास के दौरान 'भारत आओ वर्ष' के उद्घाटन में भी भाग लिया। 2 फरवरी को विदेश मंत्री महोदया ने बैठक के दौरान अतिरिक्त समय में रूस के विदेश मंत्री श्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात करने के अलावा रूस - भारत - चीन की 13वीं त्रिपक्षीय विदेश मंत्री बैठक में भी भाग लिया।

सीमा प्रश्न पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों अर्थात् राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल तथा राज्य काउंसलर श्री यांग जिची के बीच वार्ता के 18वें चक्र का आयोजन नई दिल्ली में 23 मार्च, 2015 को हुआ। दोनों पक्ष सीमा क्षेत्रों में शांति एवं अमन-चैन बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर सहमत हुए जो द्विपक्षीय संबंधों के सतत विकास की एक पूर्वापेक्षा है। दोनों पक्ष रेलवे, स्मार्ट शहर, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास, स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा तथा विनिर्माण क्षेत्र जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों का और विस्तार करने के लिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग की यात्रा द्वारा प्रदान की गई गति को और सुदृढ़ करने पर सहमत हुए। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि भारत के राज्यों एवं चीन के प्रांतों के बीच सिस्टर सिटी एवं सिस्टर प्रोविंस तंत्र के माध्यम से बढ़ते संपर्क द्विपक्षीय संबंधों को गहन करने में

महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दोनों पक्षों ने आपसी हित के क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान - प्रदान किया तथा वे आतंकवाद की खिलाफत, समुद्री सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, संयुक्त राष्ट्र सुधार तथा असैन्य परमाणु ऊर्जा सहयोग पर अपने परामर्शों को बढ़ाने के लिए सहमत हुए।

चीन से पार्टी नेताओं तथा भारत से राज्यों के मुख्यमंत्रियों के उच्चस्तरीय आदान - प्रदान को सुगम बनाने के लिए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के अंतर्राष्ट्रीय विभाग तथा विदेश मंत्रालय के बीच वर्ष, 2004 से एक विशेष व्यवस्था की गई है। । चीन की कम्युनिस्ट पार्टी तथा भारत में राजनीतिक दलों के बीच पार्टी दर पार्टी आदान - प्रदान नियमित रूप से होता है

वाणिज्यिक एवं आर्थिक संबंध :

पिछले कुछ वर्षों में व्यापार एवं आर्थिक संबंधों में तेजी से प्रगति हुई है। भारत - चीन द्विपक्षीय व्यापार, जो 2000 में मात्र 2.92 बिलियन अमरीकी डालर था, 2008 में बढ़कर 41.85 बिलियन अमरीकी डालर पर पहुंच गया जिससे संयुक्त राज्य अमरीका को प्रतिस्थापित करते हुए माल के व्यापार में चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार बन गया। वर्ष 2014 तक डी जी सी एण्ड आई एस के आंकड़ों के अनुसार भारत - चीन द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य 71.59 बिलियन अमरीकी डालर था। भारत की ओर से चीन को निर्यात का मूल्य 13.30 बिलियन अमरीकी डालर पर पहुंच गया, जबकि चीन द्वारा भारत को निर्यात का मूल्य 58.29 बिलियन अमरीकी डालर था। तथापि, चीन के मुकाबले में आज भी भारत बढ़ते व्यापार घाटे का सामना कर रहा है। 2014 में व्यापार घाटा 44.99 बिलियन अमरीकी डालर था। व्यापार के अलावा भारत चीन से परियोजना निर्यात के लिए भी सबसे बड़े बाजारों में से एक है। इस समय, 60 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक मूल्य की परियोजनाएं निष्पादन के अधीन हैं। चीन के आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर, 2014 तक भारत में चीनी निवेश 2.763 बिलियन अमरीकी डालर था, जबकि चीन में भारतीय निवेश 0.564 बिलियन अमरीकी डालर था।

भारत और चीन के बीच सांस्कृतिक संबंध : सततता की परंपरा

सांस्कृतिक आदान प्रदान का इतिहास

भारत और चीन दोनों ही समाज मात्र नहीं हैं; वे सभ्यताएं हैं। हम सटीक रूप में यह नहीं जानते हैं कि कब और कैसे उन्होंने अपने सांस्कृतिक तत्वों का आदान प्रदान करना शुरू किया, परंतु हम जो जानते हैं वह यह है कि इनका विकास समानांतर रूप में हुआ है और मानव इतिहास के शुरुआत से ही इनकी साझी सांस्कृतिक परंपराएं हैं और साझा करने की यह परंपरा तभी से चली आ रही है।

बौद्ध धर्म के प्रसार से पूर्व भी 1500 - 1000 ईसा पूर्व में शांगझोऊ सभ्यता तथा प्राचीन वैदिक सभ्यता से संकल्पनात्मक एवं भाषाई आदान प्रदान के कुछ साक्ष्य मिलते हैं। उदाहरण के लिए, चीन में "वुमिंगझी" (अनामिका) को संस्कृत एवं पाली में अनामिका कहा जाता है। इसी तरह चीन के लोगों का हवाला देते हुए भारत के कुछ प्राचीन साहित्य में "चीन" का उल्लेख मिलता है। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के महाभारत में चीन का उल्लेख मिलता है। मौर्य वंश (350-283 ईसा पूर्व) के चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में चीनी सिल्क का उल्लेख "चिनामसुका" (चाइनीज सिल्क ड्रेस) और "चिनापट्टा" (चाइनीज सिल्क बंडल) के रूप में किया है। इसी तरह झांग कियान और सीमा कियान के महान इतिहासकार के रिकार्ड में "शेंदू" का उल्लेख मिलता है, हो सकता है कि यह संस्कृति में "सिंधु" का द्योतक हो।

ईसा पूर्व छठीं शताब्दी में कनफ्यूशियस एवं शाक्य मुनि के जन्म से दोनों सभ्यताओं के बीच आदान प्रदान के एक नए युग की शुरुआत हुई। ईसा पूर्व 256 में उनके धर्मांतरण के बाद सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार से दोनों सभ्यताएं और भी करीब आ गईं। अशोक की द्विभाषी (खरोष्ठी और ग्रीक) राजाज्ञा चीन और मध्य एशिया की दिशा में बौद्ध धर्म के विस्तार का संकेत देती है। सम्राट कनिष्क के शासनकाल के दौरान पहली शताब्दी ए डी में यह रुझान जारी रहा। उनके साम्राज्य, जिसकी राजधानी पुरुषपुर में थी जो अब पाकिस्तान के पेशावर में है), ने ऐतिहासिक सिल्क रूट पर बौद्ध तीर्थयात्रियों एवं विद्वानों की यात्रा को संभव बनाया। कश्यप मतंग और धर्मरत्न ने लोयांग में हाइट हॉर्स मठ को अपना निवास स्थान बनाया। सिल्क रूट पर खोतन तर्पण और कच्छ बौद्ध धर्म तथा भारत - चीन आदान प्रदान के प्रमुख केन्द्र बन गए। महान विद्वान कुमार जीवा ने चनगान (वर्तमान शियान) ने महान बौद्ध कंकलेव में बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथों का संग्रहण करने एवं अनुवाद करने का प्रयास शुरू किया, जहां उन्होंने 413 ईसवी में अपनी मृत्यु तक प्रवास किया और बौद्ध धर्म की 98 प्रमुख प्रामाणिक कृतियों का चीनी भाषा में अनुवाद करने में सफलता प्राप्त की। बड़े पैमाने पर ऐसा माना जाता है कि वह चीनी दर्शन में महायान और माध्यमिका सिद्धांत को लाने के लिए जिम्मेदार हैं। 5वीं शताब्दी ए डी की शुरुआत में धर्मक्षेमा नामक एक भारतीय बौद्ध विद्वान चीन गए और अपने साथ महापरिनिर्वाण सूत्र लेकर गए जिसे वर्ष 415 ए डी के आसपास चीनी भाषा में अनूदित किया

गया। इस बीच सिल्क रूट से होते हुए भारत के लिए चीनी तीर्थ यात्री फाह्यान प्रस्थान कर चुके थे तथा 405 ए डी में यहां पहुंचे। बटुओ (464-495 ए डी) और बोधी धर्म ने चीन का दौरा किया; शुआन झांग (604 ए डी) और प्रथम चिंग प्रतिष्ठित नालांदा विश्वविद्यालय में छात्र थे। कुल मिलाकर सिल्क रूट ने भारत - चीन सांस्कृतिक, वाणिज्यिक एवं प्रौद्योगिकीय आदान प्रदान को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने हमें प्राचीन पर्सिया और भूमध्य रेखा के देशों के लोगों से भी जोड़ा।

दोनों सभ्यताओं ने वैज्ञानिक ज्ञान को भी साझा किया। 8वीं शताब्दी में भारतीय ज्योतिर्विद आर्यभट्ट के खगोलीय संकेतों को "कैयुआन झाङ्गिंग" नामक पुस्तक में चीनी भाषा में अनूदित किया गया, जिसे भारतीय वंशज के चंगान में गौतम सिद्धा नामक एक ज्योतिर्विद द्वारा संकलित किया गया। यह भी माना जाता है कि उन्होंने चीनी भाषा में नबाग्रह कलेंडर को भी अनूदित किया। मिंग साम्राज्य के दौरान नेविगेटर जनरल झिंग का 15वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कालीकट में पहुंचना भी भारत के साथ चीन के प्राचीन समुद्री संपर्क का प्रमाण है।

सांस्कृतिक आदान प्रदान का आधुनिक चरण

स्वराज के लिए हमारे संघर्ष के काल के दौरान हमारा आदान प्रदान जारी रहा। 20 वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में नोबल पुरस्कार विजेता रवीन्द्रनाथ टैगोर ने 1924 और 1929 में दो बार चीन का दौरा किया। 1911 से चीन के विद्वानों एवं बुद्धिजीवियों ने भारत का दौरा करना जारी रखा है तथा टैगोर के जीवन, कृतियों और दर्शन की समीक्षा कर रहे हैं।

डाक्टर द्वारकानाथ कोटनिस, जिनके नश्वर अवशेष हेबई प्रांत में उत्तर चीन शहीद स्मारक कब्रिस्तान में पड़े हैं, ने चीन - जापान युद्ध के दौरान चीन के लोगों की सेवा करते हुए अपने जीवन की आहुति दे दी। 5 भारतीय डाक्टरों के चिकित्सा दल के अंग के रूप में वह 1938 में चीन गए तथा घायल सैनिकों का उपचार करने के लिए मोबाइल क्लीनिकों में काम किया। अंततः उन्हें एट्थ रूट आर्मी द्वारा निर्मित डाक्टर बेथुने इंटरनेशनल पीस हास्पिटल के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। 2 जुलाई 2015 को डाक्टर कोटनिस की बहन डाक्टर मनोरमा कोटनिस का निधन हो गया।

भारत और चीन दोनों ने लगभग एक ही समय पर अर्थात् भारत ने 1947 में और चीन जनवादी गणराज्य ने 1949 में स्वतंत्र शासन की अपनी यात्रा शुरू की। 1955 में तत्कालीन उप विदेश

मंत्री डाक्टर ए के चंदा के नेतृत्व में पहले भारतीय सांस्कृतिक शिष्टमंडल ने चीन का दौरा किया, जिसका चीन के नेताओं एवं जनता द्वारा उनके दौरे के दौरान गर्मजोशी से स्वागत किया गया। 1960 और 1970 के दशकों में राजकपूर की दो बीघा जमीन, आवारा और श्री 420 और नूरी जैसी बॉलीवुड की फिल्मों से चीन की जनता के दिलो दिमाग में भावनात्मक रिश्ता विकसित हुआ। आज भी इन फिल्मों के गानों को लोग चलते फिरते गुनगुनाते हैं। हाल के वर्षों में पीके, 3 इडियट्स तथा दि लाइफ ऑफ पाई जैसी फिल्मों का भरपूर स्वागत हुआ है।

वर्ष 1988 से दोनों देश सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के माध्यम से अपने लोगों को एक साथ ला रहे हैं। प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह की अक्टूबर, 2013 में चीन यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित नवीनतम सी ई पी में सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग का प्रावधान है जिसमें अभिनय कलाकारों, अधिकारियों, लेखकों, अभिलेखागारवेत्ताओं एवं पुरातत्वविदों की यात्राओं, सांस्कृतिक महोत्सवों, फिल्म महोत्सवों के आयोजन तथा मास मीडिया, युवा कार्यक्रम एवं खेल के क्षेत्र में आदान - प्रदान शामिल है।

2003 में, प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लुयांग, हेनान प्रांत में भारतीय शैली का एक बौद्ध मंदिर निर्मित करने की प्रतिबद्धता की थी तथा राष्ट्रपति प्रतिभा देवीसिंह पाटिल ने मई, 2010 में चीन की अपनी यात्रा के दौरान इस मंदिर का उद्घाटन किया। फरवरी, 2007 में, नालंदा में जुआनजंग स्मारक का उद्घाटन किया गया। जून, 2008 में, संयुक्त डाक टिकट जारी किए गए, एक डाक टिकट में बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर को दर्शाया गया तथा दूसरे डाक टिकट में लुयांग स्थित सफेद घोड़ा मंदिर को दर्शाया गया। 2003 में पीकिंग विश्वविद्यालय में भारतीय अध्ययन केन्द्र स्थापित किया गया। शेनझोंग विश्वविद्यालय, जिनान विश्वविद्यालय, फुडान विश्वविद्यालय, गुआंगडोंग विश्वविद्यालय में तथा शंघाई अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन विश्वविद्यालय में भारतीय अध्ययन / हिंदी पीठों की भी स्थापना की गई है। भारत - चीन राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ वर्ष 2010 में दोनों देशों में पूरे उत्साह के साथ मनाई गई।

भारत और चीन के बीच युवाओं के शिष्टमंडल का आदान - प्रदान वर्ष 2007 से जारी है। नवंबर, 2006 में चीन के राष्ट्रपति हु जिंताओं की भारत यात्रा के दौरान दोनों पक्ष युवाओं के शिष्टमंडल के परस्पर आदान - प्रदान के लिए एक पंचवर्षीय कार्यक्रम शुरू किया था। इस संदर्भ में, चीन ने अगले पांच वर्षों में भारत से 500 युवाओं को आमंत्रित किया था। आगे चलकर, दिसंबर, 2010 में चीन के प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ की भारत यात्रा के दौरान, दोनों पक्ष अगले पांच वर्षों में युवाओं के आदान - प्रदान की गतिविधियों को जारी रखने पर सहमत हुए। हर साल चीनी पक्ष द्वारा भी पारस्परिक यात्राएं की गईं। सितंबर, 2014 में, चीन के राष्ट्रपति श्री शी जिनपिंग की भारत यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने परस्पर समझ बढ़ाने में युवाओं के आदान -

प्रदान के महत्व को स्वीकार करते हुए 2015 से 2019 के दौरान 200 युवाओं वार्षिक आदान - प्रदान को जारी रखने पर सहमति व्यक्त की।

प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री ली किचियांग की वर्ष 2013 में यात्रा के दौरान दोनों नेताओं ने वर्ष 2014 को भारत और चीन के बीच मैत्रीपूर्ण विनिमय वर्ष के रूप में घोषित किया। इस विशेष वर्ष के अवसर पर वर्ष 2014 के दौरान चीन के 12 शहरों में भारत महोत्सव की झलकियों का आयोजन किया गया जिसमें भारतीय अभिनय कलाओं, आधुनिक भारतीय कलाकारों की प्रदर्शनियों को प्रदर्शित किया गया जहां दोनों देशों के बीच बौद्ध संपर्क को दर्शाया गया, खाद्य एवं फिल्ममहोत्सव आयोजित किए गए। इस महोत्सव के अंग के रूप में कला क्षेत्र, कथक केंद्र द्रूप संगीत नाटक अकादमी तथा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा प्रायोजित एक बालीवुड मंडली ने चीन का दौरा किया। संगीत नाटक अकादमी ने शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पांच सिद्धांतों की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर ग्रेट हाल ऑफ पीपुल में आयोजित स्वागत समारोह में अपनी कला का प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों को भारतीय प्रामाणिक व्यंजनों का स्वाद चखाने के लिए बीजिंग, किंगडाओ, शंघाई, हांगकांग जैसे शहरों में खाद्य महोत्सव का भी आयोजन किया गया। आयुष विभाग, भारत सरकार के सहयोग से बीजिंग, शंघाई और दाली में जुलाई, 2014 में योग महोत्सव का भी आयोजन किया गया। हांगकांग, शंघाई तथा चेंगदू जैसे शहरों में बौद्ध कला प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से बीजिंग, हांगझू, ग्वांगझू, किंगडाओ, हांग कांग तथा झियान जैसे शहरों में भारतीय फिल्म महोत्सव का भी आयोजन किया गया।

दिसंबर, 2010 में चीन के प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ की भारत यात्रा के दौरान भारत और चीन के नेताओं ने एक परियोजना पर सहमति व्यक्त की जिसके तहत भारत - चीन सांस्कृतिक संपर्कों का एक विश्वकोष संकलित किया जाना है। भारत - चीन सांस्कृतिक संपर्कों के विश्वकोष का विमोचन अंग्रेजी एवं चाइनीज दोनों रूपांतरों में बीजिंग में 30 जून, 2014 को भारत के माननीय उप राष्ट्रपति की चीन यात्रा के दौरान किया गया। इस विश्वकोष में कुल 700 से अधिक प्रविष्टियां हैं जिनके माध्यम से व्यापार, आर्थिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं दार्शनिक क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच संपर्क एवं आदान - प्रदान के समृद्ध इतिहास को सारांश रूप में प्रस्तुत किया गया है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 14 से 16 मई, 2015 के दौरान चीन का तीन दिवसीय राजकीय दौरा किया। इस यात्रा से पूर्व प्रधानमंत्री मोदी ने चीन की जनता से जुड़ने के लिए अपना स्वयं का 'वीबो' हैंडल शुरू किया। इस यात्रा के ब्यौरों को सबसे पहले इस वीबो हैंडल के माध्यम से आम जनता के साथ साझा किया गया तथा तब से यह हैंडल चीन के नेटिजन के बीच काफी

लोकप्रिय हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा प्रतीकात्मकता की दृष्टि से काफी समृद्ध थी तथा इसने भारत और चीन के बीच बढ़ती घनिष्ठता को प्रदर्शित किया। पहली बार राष्ट्रपति शी जिंगपिंग ने किसी विदेशी नेता की शियान में शांशी के अपने गृह प्रांत में अगवानी करने के लिए बीजिंग से बाहर का दौरा किया। राष्ट्रपति शी प्रधानमंत्री मोदी के साथ बिग वाइल्ड गूज पगोडा भी गए - जो अपने आप में हमारी दो महान सभ्यताओं की साझी विरासत का प्रतीक है - तथा शियान सिटी वाल में एक भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया। प्रधानमंत्री ली कीक्यांग पृष्ठभूमि के रूप में टेम्पल ऑफ हैवन के विश्व विरासत स्थल के साथ योग - ताइची परफार्मेंस में प्रधानमंत्री मोदी के साथ भाग लिया, जो इस तरह का पहला कार्यक्रम था जिसमें दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संपर्क को उजागर किया गया। दोनों नेताओं ने एक सेल्फी भी ली जो वीबो पर 33 मिलियन से अधिक हिट्स के साथ वायरल हो गई। सरकार दर सरकार स्तर पर 24 करार, व्यवसाय दर व्यवसाय स्तर पर 26 एम ओ यू तथा दो संयुक्त वक्तव्यों पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें से एक जलवायु परिवर्तन पर था। जन दर जन संपर्कों का विस्तार करना और सांस्कृतिक संपर्कों में वृद्धि करना इस यात्रा के एक प्रमुख विषय के रूप में शामिल हुआ। राष्ट्रपति शी के साथ प्रधानमंत्री मोदी की ग्रेट वाइल्ड गूज पगोडा की यात्रा तथा प्रधानमंत्री ली के साथ योग - ताइची कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति इस बात के उदाहरण हैं कि हमारे नेता साझी सांस्कृतिक विरासत का उपयोग करने के कार्य को कितना महत्व देते हैं। इसके अलावा तीन नई संस्थाओं का उद्घाटन किया गया : शंघाई में गांधीवादी और भारतीय अध्ययन केन्द्र, कुनमिंग में योग महाविद्यालय और अहमदाबाद में राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता संस्थान।

11 दिसंबर 2014 को 193 सदस्यों वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा ने चीन सहित 177 देशों की अभूतपूर्व सह-प्रायोजकता के साथ सर्वसम्मति से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में स्थापित करने के संकल्प को अनुमोदित किया। अपने संकल्प में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस बात को स्वीकार किया कि योग स्वास्थ्य एवं कल्याण का एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है तथा पूरी दुनिया के लोगों के स्वास्थ्य के लिए योग करने के लाभों के बारे में सूचना का बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार होना चाहिए। भारतीय दूतावास, बीजिंग और शंघाई, गुआंगझू और हांग कांग स्थित भारतीय कॉन्सुलेट ने चीन में 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। बीजिंग, शंघाई, तियानजिन, किंगडाओ, हांग कांग, मकाऊ, गुआंगझोऊ, चेंगदू, कुनमिंग, शियामेन, वुक्शी, हांगझोऊ, वेनझोऊ और चांगझोऊ सहित चीन के 14 से अधिक शहरों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया जिसमें हजारों लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया। संगीतकार सुश्री सिकिन गाओली, अभिनेता श्री वांग बाओकियांग, श्री दु यिहेंग और स्नूकर चैंपियन श्री डिंग जुनहुई सहित चीन के अनेक सेलिब्रिटी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर

पर बधाई देते हुए तथा इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए लोगों को आमंत्रित करते हुए निजी वीडियो पृष्ठांकन संदेश दिया।

भारत और चीन दोनों की संस्कृतियां एवं लोग बहुत जीवंत हैं। बौद्ध धर्म, शुआन झांग, टैगोर, डाक्टर कोटनिस, नालंदा, योग और सिनेमा आदान प्रदान की हमारी लंबी परंपरा के प्रतीक मात्र हैं। ये हमारी साझी विरासत के प्रमाण हैं। शुरुआत हो चुकी है तथा 21वीं शताब्दी में गति में केवल वृद्धि हो सकती है।

शैक्षिक संबंध :

भारत और चीन ने 2006 में शैक्षिक आदान - प्रदान कार्यक्रम (ई ई पी) पर हस्ताक्षर किया जो दोनों देशों के बीच शैक्षिक सहयोग के लिए एक छत्रछाया करार है। इस करार के तहत एक - दूसरे के देश में उच्च अध्ययन की मान्यता प्राप्त संस्थाओं में दोनों पक्षों द्वारा 25 छात्रों को सरकारी छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। भारत द्वारा प्रदान की जाने वाली 25 छात्रवृत्तियां भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आई सी सी आर) द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा के दौरान दोनों देशों ने 15 मई 2015 को एक नए शैक्षिक विनिमय कार्यक्रम (ई ई पी) पर हस्ताक्षर किया है। इसमें व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में संस्थाओं के बीच सहयोग में वृद्धि, उच्च शिक्षा की संस्थाओं के बीच साझेदारी आदि का प्रावधान है।

इसके अलावा, चीन के छात्रों को केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा में हिंदी सीखने के लिए हिंदी की पढ़ाई करने के लिए हर साल छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। वर्ष 2014-15 के लिए चीन के 7 छात्र इस स्कीम के तहत आगरा में पढ़ाई में कर रहे हैं।

2010 में, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी बी एस ई) के पाठ्यक्रम में मंडारिन चाइनीज को विदेशी भाषा के रूप में शुरू करने का निर्णय लिया गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा कंप्यूशियस संस्थान के बीच अगस्त, 2012 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया जहां दोनों हस्ताक्षरकर्ता शैक्षिक स्टाफ, शिक्षकों एवं प्रशिक्षणार्थियों का आदान - प्रदान करने और भारत में स्कूलों में द्वितीय भाषा के रूप में मंडारिन चाइनीज पढ़ाने के लिए प्रणाली एवं संरचना पर सूचना का आदान - प्रदान करने के लिए सहमत हुए। इस एम ओ यू के अंग के रूप में, चीन के 22 शिक्षकों का पहला बैच वर्ष 2014 के पूर्वार्ध से एक साल के लिए चुनिंदा सी बी एस ई स्कूलों में पढ़ा रहा है।

दोनों देशों के बीच शिक्षा क्षेत्र में सहयोग की वजह से चीन में भारतीय छात्रों की संख्या बढ़ गई है। 2014 की स्थिति के अनुसार, चीन के विभिन्न विश्वविद्यालयों में विभिन्न विषय क्षेत्रों में 10491 भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे थे। इसी तरह, चीन के लगभग 2000 छात्र भारत में विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं में पढ़ाई कर रहे हैं।

उपयोगी संसाधन :

भारतीय दूतावास, बीजिंग की वेबसाइट : ..

अगस्त, 2015